

भारत पुर्नोत्थान अभियान (आई.आर.आई.)
के संस्थापक सदस्य :-

1. न्यायमूर्ति आर० सी० लहोटी,
भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश, मा० उच्चतम न्यायालय
2. श्री जे० एम० लिंगदोह,
भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त
3. श्री वी० के० शृंगलू,
भूतपूर्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
4. डा० हरी गौतम,
भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
5. एयर चीफ मार्शल, एस० कृष्णा स्वामी
(रिटायर्ड), भूतपूर्व वायुसेना अध्यक्ष
6. श्री जे० एफ० रिबीरो,
भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक, पंजाब एवं सी.पी., मुम्बई
7. श्री एस०ए०टी० रिजवी,
भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार
8. प्रो० एच० सी० पाण्डेय,
वाइस चान्सलर (विशिष्ट)
9. डा० एन०सी० सक्सेना,
भूतपूर्व सदस्य सचिव, योजना आयोग
10. श्री प्रकाश सिंह,
भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, उ०प्र०
11. प्रो० एस०के० दुबे,
निदेशक, आई.आई.टी., खडगपुर
12. श्री शरद प्रधान, पत्रकार
13. श्री एस०आर० लाखा, आई०ए०एस०
14. श्री वी०एस० पाण्डेय, आई०ए०एस०
15. श्री राजू शर्मा, आई०ए०एस०
16. श्री सुनील कुमार, आई०ए०एस०
17. श्रीमती रेणुका कुमार, आई०ए०एस०
18. श्री जसवीर सिंह, आई०पी०एस०

भारत पुर्नोत्थान अभियान

(सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने हेतु मंच)

भारत पुर्नोत्थान अभियान एक पूर्णतः
अराजनैतिक सामजिक मंच है, जो कुछेक
व्यक्तियों द्वारा अपने अन्तःकरण से प्रेरित
होकर समाज में व्याप्त अव्यवस्था के विरुद्ध
सक्रिय योगदान प्रदान करने का एक प्रयास है।

पो. बाक्स-291, जी.पी.ओ., नई दिल्ली-110 001
ई-मेल : irinitiative@gmail.com
वेब साइट : www.iri.org.in

कृपया विचार करें

- चालीस के दशक में हमारे साथ ही विदेशी शासन के चंगुल से मुक्त हुए कई अन्य देश हमसे काफी आगे क्यों चले गये?
- इन सभी देशों ने अशिक्षा, गरीबी, बीमारी एवं बेरोजगारी जैसी अपनी मूलभूत समस्याओं से कमोवेश मुक्ति पा ली, परन्तु हम लगभग 60 वर्ष बाद भी इन समस्याओं से बुरी तरह से ग्रस्त हैं।
- हमारे यहाँ कागज पर सभी व्यवस्थायें मौजूद हैं, लेकिन धरातल पर उसका कुछ ही अंश लागू है।
- न्याय एवं शान्ति व्यवस्था जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी हम कमोवेश विफल ही रहे हैं।
- आज देश का कानून केवल गरीब एवं कमजोर तबकों के लिए ही लागू है। शक्तिमान एवं धनी अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं तथा कानून उन्हें रोक पाने में विफल रहा है।
- गरीब, असहाय एवं निर्बल तबके के लोगों के लिए अपना आत्म-सम्मान एवं इज्जत बचा पाना काफी कठिन है।
- जन सामान्य का कोई वैध कार्य भी बिना रिश्वत के सम्पन्न नहीं होता।
- बिना सिफारिश के अब पुलिस थानों में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती है चाहे घटित अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो।
- सही ढंग से जीवन यापन कर पाना अब नितांत मुश्किल होता जा रहा है, असामाजिक तत्व कभी भी किसी का अपमान बेधड़क कर सकते हैं।
- गुण्डा टैक्स, रंगदारी टैक्स दिये बिना व्यापार एवं कोई कारोबार कर पाना अधिकांशतः सम्भव नहीं है।
- असामाजिक एवं अपराधिक तत्व शासन एवं प्रशासन पर अपनी पकड़ इस कदर मजबूत कर चुके हैं कि जन मानस उनका सामान्यतः विरोध कर पाने की स्थिति में स्वयं को नहीं पाता।
- कुछ अपवादों को छोड़कर जन सामान्य के लाभार्थ लागू की गई योजनाओं हेतु अर्बित धन का बड़ा भाग भ्रष्ट नौकरशाही, नेताओं और बिचौलियों के हत्थे चढ़ जाता है।
- भ्रष्ट कर्मचारियों, नौकरशाहों एवं राजनैतियों की पौबारह है जबकि ईमानदार, निष्ठावान लोग चाहे वह जिस भी पेशे में हों, वह आज तिरस्कृत हो रहे हैं।
- कानून के राज के स्थान पर व्यक्ति विशेष की इच्छाओं का राज स्थापित है।

क्या यह सब इसलिए है, क्योंकि हमारे पास धन की कमी है।

- उपलब्ध आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि देश को समस्याओं के समाधान हेतु धन की कोई कमी नहीं है।
- न्याय व्यवस्था, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किसी अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है बल्कि केवल इन विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कुशासन को समाप्त करना है।
- केवल एक वर्ष में देश में टैक्स की हो रही चोरी को रोक देने मात्र से, विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार कम से कम दो लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है जिसके चलते तीन वर्षों के अन्दर ही देश में बिजली कटौती का नामोनिशान नहीं रहेगा, प्रत्येक गाँव में पूर्णतः सुसज्जित स्कूल स्थापित हो जायेंगे, पेय जल, स्वास्थ्य एवं सड़क की समस्या का समाधान हो जायेगा।

अतः समस्या के मूल में है कुशासन, गैर-जिम्मेदार एवं संवेदन विहीन प्रशासनिक व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार और जब तक इस पर कुठाराघात नहीं होगा तब तक स्थितियां बदलने वाली नहीं हैं।

हमारा मानना है कि आज देश में कुछ मुट्ठीभर भ्रष्ट व्यभिचारियों एवं समाज विरोधी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक व्यापक जन आन्दोलन की आवश्यकता है। मुट्ठीभर भ्रष्टों एवं व्यभिचारियों के विरुद्ध देश में आज भी करोड़ों लोग कानून का राज एवं ईमानदार एवं स्वच्छ शासन प्रशासन की इच्छा रखते हैं। प्रश्न केवल संगठित होकर इन मुट्ठीभर आततायियों को परास्त करने भर का है। रखते हैं।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन रह चुके एवं निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों ने एक साथ आकर देश के सार्वजनिक जीवन में शुद्धता एवं शुचिता लाने का प्रयास भारत पुनोत्थान अभियान के नाम से प्रारम्भ किया है।

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, समाज के अलग-अलग वर्गों से आये इन व्यक्तियों द्वारा यह महसूस किया गया कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता एवं ईमानदारी में भारी गिरावट आयी है, फलस्वरूप चरित्र बल एवं नैतिकता का पतन हुआ है, जिसका कुप्रभाव सामान्य जनता विशेष रूप से युवाओं पर पड़ रहा है।

Founding members of IRI are :

1. **Justice R. C. Lahoti,**
Former Chief Justice of India
2. **Shri J. M. Lyngdoh,**
Former Chief Election Commissioner, India
3. **Shri V. K. Shunglu,**
Former Comptroller and Auditor General of India
4. **Dr. Hari Gautam,**
Former Chairman, University Grants Commission
5. **Air Chief Marshall, S. Krishnaswamy,**
(Retd.) Former Chief of Air Staff
6. **Shri J. F. Ribeiro,**
Former DGP, Punjab & C.P., Mumbai
7. **Shri S. A. T. Rizvi,**
Former Secretary, Government of India
8. **Prof. H. C. Pandey,**
Vice Chancellor, Emiratus
9. **Dr. N. C. Saxena,**
Former Member Secretary,
Planning Commission, India
10. **Shri Prakash Singh,**
Former DG B.S.F., DGP UP, DGP Assam
11. **Prof. S. K. Dube,**
Director, IIT, Kharagpur
12. **Shri Sharat Pradhan,** Journalist
13. **Shri S. R. Lakha,** I.A.S.
14. **Shri V. S. Pandey,** I.A.S.
15. **Shri Raju Sharma,** I.A.S.
16. **Shri Sunil Kumar,** I.A.S.
17. **Mrs. Renuka Kumar,** I.A.S.
18. **Shri Jasvir Singh,** I.P.S.

INDIA

Rejuvenation Initiative

(A Forum for Probity in Public Life)

“India Rejuvenation Initiative (IRI) (Bharat Punarotthan Abhiyan), a purely non-political and social forum, is an effort of conscientious individuals who feel pained and also inspired, not to sit back but to act.”

P.O. Box No. 291, GPO, New Delhi - 110 001
E-mail : irinitiative@gmail.com
Website : www.iri.org.in

Please consider the following :

- Why countries which became independent with India in the forties have marched far ahead.
- These countries more or less overcame most of their basic problems such as illiteracy, poverty, unemployment and health related etc., but even after a span of almost sixty years, we have not been able to remedy our problems.
- System has become so corrupt that unless palms of officials are greased, one can't even get what is due to him legally.
- It's difficult to live life with honor and dignity. Anti-social elements can insult anyone any time with impunity.
- The criminal justice system does not act unless bribe is paid at the police stations however heinous the crime committed may be.
- Most of the money meant for development schemes end up in the pockets of corrupt government servants, politicians and middle men.
- The corrupt rule and the honest live the life of humiliation and obscurity.
- Instead of rule of law now it is the rule of a few individuals who control the levers of power.
- Every now and then, cases of corruption at the top levels are being reported, but the culprits move around with impunity and shamelessly. Protection is provided to these elements by those who run the show.

It is almost impossible for anyone to engage in any kind of trade, occupation or business without paying Hafta, Goonda tax or Rangdari.

Do we lack Funds?

- According to available statistics, there is no paucity of funds to tackle these problems.
- There is no need for any additional funds for bringing about administrative and police reforms, and to make system citizen friendly. We only need to check corrupt practices and misgovernance eroding the system.
- According to one estimate, if only tax collection machinery performs its duties honestly, additional Rs. Two lack crore would be generated in the process every year, which is adequate to take care of all the major infrastructure related problems such as electricity, education, health services, roads, drinking water etc. in a period of just about three years.

The root of this problem, therefore, lies in misgovernance, irresponsible and unaccountable administration and corruption. Unless they are dealt with sternly, it would be difficult to arrest the situation.

Should we all sit back and helplessly watch this situation deteriorate further?

Drawn from various walks of life, cross sections of society, they feel deeply concerned at the sharp deterioration of probity in public life associated with the fall in moral and ethical values and demoralization of the public more specifically the youth. They have put their minds together and decided to take collective affirmative action to arrest this trend in the short run and reverse it in the long run. The IRI seeks to focus public attention and mobilize public opinion on ways and means to check corruption, lack of accountability and inefficiency and ensure probity in public life.